

[Shri Mukunda Mandal]

it is reported CBI was informed of the matter, they did not involve themselves directly in investigating the matter yet. Bank authority in the meantime has given appointment to a retired D.S.P. of CBI as a Special Officer of the Bank. Employees of the bank are being harassed in sanctioning loan from S.P.F. and being asked to see C.B.I. Office by letters without giving the purpose of mentioning the name of C.B.I. directly. The Bank authority is reluctant to investigate the whole matter. They want to save the officials who are responsible for the fraud and forgery continued for several years involving few lakhs of rupees.

(iii) REPORTED DAMAGE CAUSED BY HAIL-STORM AND HEAVY RAINS IN HIMACHAL PRADESH

श्री बालक राम (गिमला) : स्पीकर साहब, नियम 377 के तहत आपने मुझे देश के एक पिछड़े राज्य पर अभी हाल में तूफान और भोलों से पैदा हुए मानी संकट की तरफ लोक मभा तथा सरकार का ध्यान दिलाने का जो मौका दिया है इसके लिये मैं आपका धन्यवादी हूँ। इस मवाल पर चर्चा करने से पहले मैं मंत्री महोदय, श्री मुरजीत सिंह बगनाला जी का, पिछले साल हिमाचल प्रदेश में भारी बाढ़ से हुए नुकसान के लिये सैन्ट्रल गवर्नमेंट से सबसिडी का गेहूँ दिया गया है, उसके लिये मैं और मेरे हिमाचल प्रदेश की जनता शुक्रगुजार है।

मान्यवर, दूर दूर जगहों से आने वाले लोगों से प्राप्त हुए पत्रों तथा तारों और प्रेस रिपोर्ट्स से यह माफ जाहिर हुआ है कि साल के आखिर में तथा अप्रैल के पहले हफ्ते के दौरान समय-समय पर भारी भारी और भोलों से वहाँ की रबी फ़सल और सेब की फ़सल को करोड़ों की लागत का नुकसान हुआ है। जिला शिमला, कुलु और जिला सिरमौर में सेब के बागीचों को भोलों से इतना नुकसान हुआ है कि मुश्किल से किसानों

को 25 फ़ीसदी सेब की फ़सल मिलेगी। शिमला जिले के ऊपरी हिस्से में तो भारी और भोलों की बरसात उस समय हुई, जब सेब के पौधों पर फूल लगे, और भारी, तूफान और भोलों से सर्वा फूल झड़ गये। जाहिर है कि जब फूल ही झड़ गये, तो फल वहाँ से भागेंगे। मंत्री महोदय इस बात को बखूबी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सेब बागान ही वहाँ की माली हालत की रोड़ की हड्डी हैं। सेब की फ़सल पर ही वहाँ के किसानों की ज़िन्दगी मुहम्मिर करनी है। अगर सेब न हों या सेब मम्न बिके, तो उस का सीधा प्रभर उन की माली हालत पर पड़ता है और उन्हें मजदूर होकर मजदूरी करनी पड़नी है। बदकिम्मी में इस साल तूफान और भोलों से मेरे हम आठ लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और यहाँ के लोगों का भविष्य अन्धेरे में हो गया है।

हर साल हिमाचल प्रदेश कीमतन 50 लाख सेब की पेटिया बाहर भेजता है। हर सेब की पेटि की उत्पादन लागत 25 रुपये होती है। इस लागत में साल भर की मेहनत, खाद, मजदूरी और भाड़ा वगैरह शामिल हैं। पैदावार लागत काटने के बाद पत्रह, बीस याया फ़ी-पेटि ही किसान को बचना है। इस नैचरल कैलिमिटी के बाद मुश्किल से 25 फ़ीसदी सेब की फ़सल मिलन का आम्नाजा है। इस तरह से लगभग 50 लाख पेटियों में से 10 लाख पेटियों का आम्नाजा है। 8 करोड़ रुपये की लागत की फ़सल भोलों और भारी से बर्बाद हुई है।

अब हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। लोग मेहनत-मजदूरी के लिए अटक रहे हैं। वहाँ कोई प्रोजेक्ट या कारखाना नहीं है, जहाँ लोग मजदूरी कर के अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकें। उनकी रोड़ी रोटी सेब ही है जो अब नहीं रही। इस हालत में उनका सामना एक क़हत जैसी हालत से होता जा रहा है।

MR. SPEAKER: You have added on many things Mr. Balak Ram.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): All harmless things, Sir..

श्री बालक राम : इस लिए मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना हूँ कि भोलों से प्रभावित इनकों के किमानों को पहले सालों में हुई सेब की फ़मल के अनुपात में सत्रमिडी दी जाये । इस इलाके के लोगों को कम कीमत वाला गेहूँ दिया जाये । किमानों को लॉग-टर्म या मीडियम-टर्म लोन दिलाने का प्रबन्ध किया जाये । हर नहसील में जल्दी कोई विकास प्राजेक्ट या कारखाना खोला जाये, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके ।

मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी शिमला पार्लियामेन्टरी कान्ट्रीट्रयुल्सी के लोगों की दर्दनाक हालत पर विचार करते हुए मेरे इन सुझावों को जल्दी लागू करने का इन्तजाम करेगी ।

MR. SPEAKER: You are adding further and you make it difficult for me to select your Rule 377 notices hereafter. I will make a note of it, Mr. Balak Ram. Making further additions will make it difficult for me to select your Rule 377 Notices later.

(iv) REPORTED CONTINUING PROBLEM OF REFUGEES FROM PAKISTAN OCCUPIED AREAS OF JAMMU AND KASHMIR STATE

DR. KARAN SINGH (Udhampur): Mr. Speaker, Sir, under Rule 377, I wish to raise the following matter of urgent public importance, regarding the continuing problem of refugees from Pakistan-occupied areas of the Jammu and Kashmir State.

The House is aware that following the invasion of Jammu and Kashmir by Pakistan in 1947, lakhs of people

residing in the areas which are still under Pakistan occupation were rendered homeless.

In addition, many thousands of people—mainly Harijans and other weaker sections of society—crossed over from the Sialkot border and took refuge in Jammu.

Although 30 years have elapsed, the claims of these refugees have still not been registered. The Government of India continues to claim that the reason for non-registration of the claims is due to the fact that the areas under Pakistan occupation are legally part of India.

It is of course true that as a result of the Instrument of Accession, the entire State of Jammu and Kashmir as it stood on the 15th August, 1947 is legally and constitutionally a part of India. But it cannot be the intention to penalise the refugees because of our own inability to get the aggression vacated.

There is the additional problem of the refugees from the Chamb areas which passed under Pakistan occupation during the 1971 war, despite the impressive victory that we won.

The House will be surprised to know that refugees from Pakistan occupied Kashmir have not yet been granted the proprietary rights of the land allotted to them in the State, nor have their claims for compensation been duly registered.

As far as the refugees from the Sialkot sector are concerned, they do not yet have the vote in elections to the State Assembly, although they have been living in the State for over two generations now.

I would urge that the Government of India should look into this entire question with sympathy and understanding so that the genuine demands of the refugees are met as early as possible.